श्री बलमदेव आनन्द पासवान : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हाल ही में बिहार में माननीय मुख्य मंत्री लालू प्रसाद जी ने जो हरिजन कालोनियां बनायी हैं, उनमें उन कालोनियों को जिसका नाम दिया जाता है उसी को पैसा दे देते हैं । जो ठेकेदार कालोनियों को बनाते हैं, वह इस तरह से बनाये हैं, आप अगर यात्रा करें तो जहां तहां ऐसी कालोनियां बनी हुई हैं । वहां रहने वाला कोई नहीं है । इसमें दो काम किये हैं । जिसके नाम से कालोनीयां बन रहे हैं उसी को पैसा दे देते हैं और वे अपने ढंग से बना रहे हैं, और उसमें उसकी पत्नी का नाम भी होता है । दोनों, पति-पत्नी के नाम से हो जाय तो दोनों में एकता रहे, इसलिये दोनों के नाम से कालोनी बन जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि जो मकान बना रहे हैं उन्हीं के नाम से पैसा दिया जाये क्योंकि ठेकेदार आठ हजार, छ हजार में मकान बनाते हैं और वे मकान गिर जाते हैं और उसमें रहने वाले हरिजन मर जाते हैं । ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इंदिरा आवास योजना में किसी प्रकार से ठेकेदार बहाली की व्यवस्था नहीं है । जो उपभोक्ता हैं, वे स्वयं मकान बनायेंगे, उनको सहायता की राशि दी जाती है और आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य सरकार से सामान उपलब्ध कराया जाता है । मकान स्वयं उपभोक्ता बनाते हैं । राज्य सरकार की हो सकता है अपनी योजना हो, जिसमें यह काम ठेकेदारों से कराते हों लेकिन इंदिरा आवास योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । इसकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है । लेकिन अगर माननीय सदस्य शिकायत देंगे और इंदिरा आवास योजना में अगर वह होगा तो हम उसकी तजवीज अच्छी तरह से करेंगे ।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, the Minister in his reply said that the scheme of land allotment and dwelling units is meant for homeless rural people. He has also given some figures for whom it is being done i.e., SC, ST, landless and bonded labourers. I would like to know how many bonded labourers have been given dwelling places here in Delhi and also in different States. I would like to know whether the Government has any data about this.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I have no ready information with me particularly of Delhi. But in the case of rural areas if I am given a specific notice, I can obtain the figures and give them to the hon. Member.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, the Minister has replied that the scheme includes bonded labourers. I want to know how many bonded labourers have been given dwellings in the rural areas.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I said I will give it to the hon. Member.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Under the Indira Awaas Yojana, construction is going on in almost all Talukas and Districts in the rural parts. But as soon as the construction is over and the rainy season starts, it always gets demolished. Therefore, more than 75 per cent of the people are not getting any benefit out of this particular scheme. They have to go in for repairs. Particularly in Gujarat State in District Punchamahal in all talukas many houses had been constructed but they have got demolished and fallen. No investigation has been done as to why rough quality of construction material is being used. So, I would like to know whether the Government has ordered an enquiry into the rough construction of the houses and to find out whether the money was misappropriated. If so, in how many cases have they instituted such an enquiry?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, I have already mentioned that housing is a State subject and the large scale housing schemes are being implemented by different State Governments out of their own resources. In Gujarat also, the housing scheme for Halapatti, a Scheduled Caste and Scheduled Tribe community, is being implemented by that State. The unit cost under this scheme is Rs. 12,700 with 100 per cent subsidy. Now, as regards the Indira Awaas Yojana, we have a system by which the beneficiary himself constructs the house. The subsidy amount is provided to him. Materials are provided by the State Governments, as I have earlier mentioned while replying to the other question. Therefore, normally, we do not receive such complaints because the beneficiaries are very keen and concerned about the proper construction and maintenance of their houses. Construction of the house with this amount is a *pukka* construction. If there are any specific complaints as regards the Indira Awaas Yojana or the other schemes, the hon. Member may give me the details and we will consult with the Gujarat Government and ask them to find out the reasons for such things.

Employment Generation Programmes Launched by KVIC

*62. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that special employment generation programmes have been

launched by Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in many districts of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of such districts in Bihar;

(d) whether KVIC propose to give special attention to employment generating programmes in the rural areas of Bihar; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (e) One of the basic objectives of the Commission is to generate non-farm employment for weaker sections of the society in the rural areas. In addition to such normal programmes for employment, the Commission has also launched a special employment generation scheme in thirteen districts in the country. In Bihar the scheme has already commenced in Saharsa district.

The programme is being implemented in close coordination with District and Rural Development Agency (DRDA) and nationalised banks. Based upon the success of the programmes, other districts may be taken up during the Eighth Plan period.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति जी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग सम्पूर्ण देश मे खादी तथा ग्रामीण उद्योग का विकास करने वाली मूलत: एक मात्र संस्था है । मेरे गृह राज्य बिहार में भी आयोग के वर्ष 90-91 के दौरान सहरसा जिले में विशेष रोजगार सृजन कार्य शुरू किया गया था जो सिर्फ महिलाओं के लिए था । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार राज्य में ग्रामीण रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की क्या सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? तथा 90-91 के दौरान अभी तक सहरसा जिले में कितने रोजगार का सृजन हुआ है और कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा वर्तमान में उनका कैसा रोजगार चल रहा है ?

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, the programme in the Saharsa district was launched in 1991. Under this programme; 8,000 *charkhas* have been distributed and it has given employment to 8,000 lady weavers. It is expected that an additional 2,000 weavers will also procure employment through DRDA, thus providing employment to 10,000 women in this district. The estimated production is about 85,000 kgs. of yarn per month worth about Rs. 1.2 crores. The raw materials required are blended poly cotton to the extent of 90,000 kgs.; muslin, 3,000 kgs. and Dally 3250 kgs., per month. Sir, the Commission had sanctioned about Rs. 6.91 crores to the district till 1992-93. The total amount likely to be spent is Rs. 20 crores. Out of Rs. 20 crores to be spent, Rs. 8 crores will be subsidy from DRDA, Rs. 8 crores will be bank loan, Rs. 3 crores as KVIC margin money and Rs. 1 crore as interest subsidy.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति जी, रोजगार सृजन हेतु जिलों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया है और किस आधार पर चुने जाते हैं ? पिछड़ेपन का मापदण्ड ऐसे जिलों को चुनने के लिए क्या रखा गया है ? बिहार राज्य के लगभग सब जिले पिछड़े हैं जिनमें आदिवासी तथा हरिजन बहुत क्षेत्र हैं तो क्या सरकार बिहार के समस्त जिलों में रोजगार सृजन का विशेष कार्यक्रम चलाने का विचार रखती है ? बिहार में खादी एवं ग्रामीण उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, a Committee has been constituted under the chairmanship of the Secretary, Small Scale Industries with representatives from the Planning Commission, the Rural Development Ministry and other Ministries. In consultation with the State Governments, the Committee is deciding the districts where we have to implement these programmes.

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, मेरी जानकारी है कि खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से काफी अरसा पहले कमजोर वर्ग के लोगों को कपड़ा बुनने के लूम लगाने के लिए, कारखानों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान और सरकार की तरफ से ऋण दिया गया और अनेकों कारखाने लगाए गए । उनकी मंशा तो यह थी कि जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि इससे कमजोर वर्ग के लोगों को रोज़गार मिलेगा जो खेती से अलाहिदा रोज़गार है । लेकिन मेरी जानकारी यह है कि अनुदान का पैसा और बैंकों के ऋण का पैसा जिसके नाम से पैसा दिया गया उसमें और विभाग वालों ने इस पैसे का बंटवारा कर लिया । ऐसे 90 प्रतिशत कारखाने बंद हो गये क्योंकि उनमें बनाया जाने वाला कपड़ा बाजार में बिकने वाले कपड़े से मंहगा पड़ता है । इससे न तो रोज़गार किसी को मिला और सरकार का पैसा भी फंस गया । मेरे प्रश्न का भाग (क) यह है कि क्या मंत्री महोदय की जानकारी है कि कितने ऐसे कारखाने है जो बंद पड़े हैं और उनके बारे में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि जहां आपने यह कहा है कि विशेष योजना के तहत 13 ज़िलों में काम हो रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जिसमें आपकी यह विशेष योजना काम कर रही है ?

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, coming to the last point raised by the hon. Member, I want to say that in UP, we have selected Maunat Banjhan district. Regarding the money siphoned off by officers, we have not received any information. If he has any specific complaints, he can bring them to our notice. We will take appropriate action.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, खादी में बहुत से लोगों को रोज़गार की बड़ी संभावना है और महिलाएं तो और भी ज्यादा काम करती हैं । मैं उस क्षेत्र से आता हूं मधुबनी में जहां एक ग्रामोद्योग में 66000 महिलाएं काम करती हैं । प्रधानमंत्री जी संयोग से आज की बैठक में यहां हैं, मैं एक सुविधा चाहता हूं, जो एंटी पावर्टी पेटर्ज़ के लिए बैंक इंटेस्ट है उतना ही रेट आफ इंटेस्ट खादी के लिए कर दिया जाए तो खादी आगे बढ़ सकेगी, बहुत से लोगों को रोज़गार दे सकेगी । चूंकि बैंक इंटेस्ट मंत्री महोदय से होगा नहीं, इसलिए मैं आपसे ही अनुरोध करता हूं, कल भी आपने चर्चा की थी एक कमिशन की जिसकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं, आप इसमें कुछ कहें ।

प्रधान मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव) : सभापति महोदय, अभी डाल ही में खादी के सिलसिले में पूरी जांच करने के लिए, उनकी क्या क्या कठिनाइयां हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, उनका पूरा जायज़ा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है । जिसके अध्यक्ष ...(व्यवधान) ।

श्री चतुरानन मिश्र : उसमें क्या बैंक इंटेस्ट भी है जो मैंने रिक्वेस्ट किया ?

प्रधान मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव) : उस संदर्भ में इन सारी चीजों को देखने और छानबीन करने का मौका मिलेगा ।

श्री रजनी रंजन साहु : सभापति महोदय, आज की बेरोज़गारी की समस्या को देखते हुए खादी ग्रामोद्योग कमीशन जो कार्यक्रम चला रहा है वह बहुत ही छोटे पैमाने पर कार्यक्रम है जबकि खादी ग्रामोद्योग के जरिये करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकता है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1985-86 तक आचार्य विनोबा जी द्वारा स्थापित खादी मिशन की तरफ से मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी ब्लाक में एक पंचायत में 300 चम्बर चर्खे स्वर्गीय ध्वजा प्रसाद साहु के नेतृत्व में चालए जा रहे थे । इस योजना से 500 रूपये से लेकर 1000 रूपये मासिक तक का सेडिशनल रोज़गार मिल रहा था । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या खादी कमीशन खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं एवं आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा स्थापित खादी मिशन के साथ तालमेल स्थापित कर रोज़गार देने की एक कम्प्रीहेंसिव योजना देश के सामने रखेंगे ?

SHRI M. ARUNACHALAM : One of the basic objectives of the Commission is to provide non-farm employment in the rural areas. Therefore, a lot of problems have come before us and the honourable Prime Minister has announced a Committee headed by himself. If the honourable Member has got any suggestion, it is welcome and the Committee will go into it and it will help us in providing more employment.

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Raju.

SHRI J. S. RAJU : Sir, I would like to know whether the new economic policy has affected the Special Employment Generation Programme launched by the KVIC and, if so, what the total number of retrenched people in this area is and if not, what the development or progress is in khadi and village industries.

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, the liberalisation policy has also helped the Khadi and Village Industries Commission in modernising the rural industries. If the honourable Member has got any suggestions, he can pass them on to us.

MR. CHAIRMAN : Mr. Hanumanthappa.

SHRI H. HANUMANTHAPPA : Sir, I come from one of these districts where the Khadi Special Programme has been taken up. Of late, khadi is piling up and khadi institutions are finding it difficult to have a market. Added to this is the fact that the State Boards are not in a position to reimburse the rebate that the khadi institutions are paying as a result of which the capital has been locked up, stocks have been locked up and the khadi institutions in turn are finding it very difficult to continue the Special Employment Programme. So, will the Government see that at least one item of textiles is reserved for the khadi field which will go a long way not only in employment generation, but also in improving khadi itself? Moreover, khadi institutions have been harassed by the labour laws also and the taxes in certain States. Will the Khadi Commission and the Expert Committe consider exempting the khadi and village industry institutions which are working in the rural areas, particularly in areas where the down-trodden people live.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Even your own Ministers do not wear khadi. How can you find a market for khadi?

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, regarding rebate, there was some problem. We have constituted a Committee consisting of varios khadi institutions and we will take into account the

point made by him and will disburse the rebate properly. The other point which the honourable Member has made is about the main terms of reference. If he has got any suggestions, he can send them to the Committee.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या खादी कमीशन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में या सदारत में किसी कमेटी का गठन हुआ है, यदि हुआ है तो क्या प्रधान मंत्री यह बताएंगे कि उसके अनुसार खादी ग्रामोद्योग कमीशन का पुनर्गठन वे कब करेंगे ? इसके कामों के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब देंगे और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : इस कमेटी का जो गठन हुआ है उसकी पार्श्वभूमि यह है कि खादी के हमारे जितने नेता, पुराने कार्यकर्ता इस देश में हैं उनमें से कई लोगों ने मुझे कहा कि यह उद्योग जरा कमजोर पड़ रहा है । अब इस बात की आवश्यकता है कि इसकी पूरी मदद की जाए और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि इन सारी बातों पर समूचा ढंग विचार नहीं करेंगे । उस संदर्भ में यहां एक सम्मेलन हुआ और उस सिलसिले में यह निर्णय लिया गया कि इन सब बातों पर समूचा विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन हो । मान लीजिए, एक हद तक एडवाइजरी है लेकिन एक हद तक हमारी तरफ से अथारिटी के साथ कहेंगे कि यह होना है, तो शायद होगा भी । यह कोई खादी कमीशन का काम नहीं करने वाला है । खादी कमीशन से पूरी तरह से हमारा तालमेल रहेगा । खादी कमीशन ही सारा काम करेगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी यह कमेटी काम करेगी । इस तरह का इसका ढांचा है ।

श्री शांति त्यागी : माननीय सभापति जी, खादी कमीशन के अन्तर्गत लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत कातने का काम करती हैं । सभापति जी, यह गरीब वर्ग की महिलाएं हैं । इनकी शिकायत यह है, माननीय मंत्री जी सुनें, कि सूत कातने के एवज में जो उजरत इनको मिलती है, वह बहुत ही कम है ।

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उनकी शिकायत को स्वीकार करेंगे, और यदि हां, तो इसके बारे में उनकी उजरत को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठायेंगे ?

माननीय मंत्री जी, इस वक्त की सरकार जो है, वह महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए कृपया, इस दिशा में आप कुछ बतायें कि आप उनकी उजरत के लिए क्या करेंगे ?

यह शिकायत लाखों गरीब महिलाओं की है । यह महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं, यह फाइव स्टार वातावरण में पैदा नहीं हुई हैं यह हरिजनों के यहां पैदा हुई हैं ।

SHRI M. ARUNACHALAM : Sir, as I have already mentioned, we have taken up this special employment programme. We are implementing it in 13 districts this year, and in 50 districts in the Eighth Five-Year Plan. As far as the wage is concerned, a Certification Committee of the KVIC is going into it. Most of the employees are part-time employees and that aspect is being looked into by the Certification Committee of the KVIC.

MR. CHAIRMAN : Question No. 63.

Export Performance

*63. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what has been the export performance during April 1992 to March 1993 and during the first quarter of the current financial year;

(b) what has been the trade balance during 1992-93 and what has been the current account deficit; and

(c) what are the projections for 1993-94 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPILES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to provisional figures, India's aggregate exports during April-March 92-93 amounted to US $ 18420 million. For April-May 1993, the latest period for which such data are available for the current year, exports are estimated at US $ 3458.58 million.

(b) Trade deficit in 1992-93 is estimated at US $ 3.3 billion. Current Account deficit is provisionaly estimated at US $ 5.2 billion.

(c) For 1993-94, export target has been fixed at US $ 22138 million, but no targets are fixed for imports. Current Account deficit for 1993-94 is tentatively projected at US $ 4.5 billion.

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, I would like to draw the attention of the Minister to part (c) of the answer. It is a very strange answer. I have asked for the figures for exports and imports for the year 1993-94, and the likely